भारतीय दूतावास, थिंपू
भारत - भूटान संबंध

भारत और भूटान के बीच राजनयिक संबंध थिंपू में भारत के रेजीडेंट प्रतिनिधि की नियुक्ति के साथ 1968 में स्थापित हुए। इससे पूर्व भूटान के साथ हमारे संबंधों की देखरेख सिक्किम में हमारे राजनीतिक अधिकारी द्वारा की जाती थी। भारत - भूटान द्विपक्षीय संबंधों की बुनियादी रूपरेखा दोनों देशों के बीच 1949 में हस्ताक्षरित मैत्री और सहयोग संधि है, जिसे फरवरी, 2007 में महामहिम जिग्मे खेसर नामगेल वांगचुच की भारत यात्रा के दौरान नवीकृत किया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

नवीकृत की गई भारत - भूटान मैत्री संधि न केवल हमारे संबंध के समकालीन स्वरूप को दर्शाती है अपितु 21वीं शताब्दी में उनके भावी विकास की नींव भी रखती है।

उच्च स्तरीय यात्राएं :

परंपरागत रूप से अनोखे द्विपक्षीय संबंध, जिसकी खासियत आपसी विश्वास एवं समझ है, इन वर्षों में मजबूत हुए हैं। यह विशेष संबंध दोनों देशों के बीच सर्वोच्च स्तरों पर नियमित यात्राओं एवं विचारों के व्यापक आदान - प्रदान के माध्यम से मजबूत हुआ है। वर्ष 2013 में कुछ उच्च स्तरीय आदान - प्रदान हुए जैसे कि भूटान नरेश महामहिम जिग्मे खेसर नामगेल वांगचुच की 64वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में भारत यात्रा। भारत के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर महामहिम नरेश एवं महारानी ने 6 से 10 जनवरी, 2014 के दौरान भारत का आधिकारिक दौरा किया। उन्होंने एक निजी यात्रा पर अक्टूबर 2014 में भारत का पुन: दौरा किया जिसमें लारेंस स्कूल, सनावर (167वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में), बोधगया और वाराणसी की यात्रा शामिल है।

प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने के बाद लियोनचेन तशेरिंग टोबगे ने 30 अगस्त से 4 सितंबर 2013 के दौरान भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा की। 6 सदस्यीय शिष्टमंडल, जिसमें विदेश मंत्री भी शामिल थे, के साथ प्रधानमंत्री टोबगे ने मनोनीत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए 25 से 28 मई 2014 के दौरान भारत का फिर से दौरा किया।

भारत के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर भूटान के प्रधानमंत्री लियोनचेन तशेरिंग टोबगे ने अपने शिष्टमंडल के साथ 10 से 18 जनवरी 2015 के दौरान भारत का आधिकारिक दौरा किया। उन्होंने अहमदाबाद में वाइब्रेंट गुजात शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया तथा गुजरात में अनेक सफल परियोजनाओं का दौरा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तथा द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने दिल्ली में भारत के माननीय राष्ट्रपति से मुलाकात की तथा अनेक मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें की। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री टोबगे ने अमूल डेयरी की विशेषज्ञता से उस समय भारत से 2000 गायें प्रदान करने के लिए अनुरोध किया जब वह

गुजरात में थे। वह बोधगया भी गए जहां उन्हें उपहार में महाबोधी वृक्ष का एक पौधा प्रदान किया गया।

गोवा में "सभ्यता से सबक" विषय पर दूसरी इंडिया आयडियाज गोष्ठी के मुख्य अतिथि के रूप में इंडिया फाउंडेशन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री टोबगे ने 13 से 17 नवंबर 2015 के दौरान भारत का दौरा किया।

भूटान की नेशनल असेम्बली के स्पीकर लिंपो जिग्मे जैंग्पो के नेतृत्व में भूटानी संसद के एक शिष्टमंडल ने 9 से 14 अगस्त 2015 के दौरान भारत का दौरा किया। शिष्टमंडल ने नई दिल्ली में संसद के एक सत्र में भाग लिया तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री वेंकैया नायडू से मुलाकात की। शिष्टमंडल ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की।

भूटान नरेश (के-5) के निमंत्रण पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 - 16 जून, 2014 को भूटान का राजकीय दौरा किया। उनके साथ इस यात्रा पर विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा विदेश सचिव भी गए थे। पदभार ग्रहण करने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा थी। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच उच्च स्तर पर नियमित आदान - प्रदान की परंपरा सुदृढ़ हुई। इस यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पांचवें नरेश और चौथे नरेश से मुलाकात की तथा पी एम टी टी के साथ बैठकें की। प्रतिपक्ष के नेता ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने 16 जून, 2014 को भूटान की संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने 600 मेगावाट की खोलोंगचू जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी तथा उच्चतम न्यायालय के भवन का उद्घाटन किया, जिसे भारत सरकार की सहायता से निर्मित किया गया है। विचारों का आदान - प्रदान करने तथा द्विपक्षीय संबंधों एवं आर्थिक सहयोग पर चर्चा करने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने नेहरू - वांगचुच छात्रवृत्ति की राशि दोगुना करके 2 करोड़ रूपए प्रतिवर्ष करने की भी घोषणा की। उन्होंने भूटान के राष्ट्रीय पुस्तकालय में तथा भूटान के सभी 20 जिलों में ई-लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए भारत सरकार की सहायता की भी घोषणा की। दोनों पक्ष अपने - अपने राष्ट्रीय हितों से संबंधित क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग एवं समन्वय जारी रखने तथा दूसरे के हित के विरूद्ध एक - दूसरे के भूभाग का प्रयोग करने की अनुमति न देने पर भी सहमत हुए।

भूटान नरेश के निमंत्रण पर भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 7-8 नवंबर, 2014 को भूटान का राजकीय दौरा किया। इस यात्रा के दौरान, उन्होंने भूटान के महामहिम नरेश के साथ द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों सहित व्यापक श्रेणी के मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने महामहिम चौथे ड्रुक ग्यालपो तथा प्रधानमंत्री लियोनचेन तशेरिंग टोबगे से भी मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति जी ने "भारत - भूटान संबंधों" पर भाषण भी दिया तथा भारत सरकार की सहायता से संचालित तीन पी टी ए परियोजनाओं अर्थात स्कूल सुधार कार्यक्रम, पूर्व - पश्चिम राजमार्ग का उन्नयन तथा विद्युत प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन / शुभारंभ किया। उन्होंने राजदूत छात्रवृत्ति कार्यक्रम की राशि दोगुना अर्थात 1 करोड़ रूपए प्रतिवर्ष से 2 करोड़ प्रतिवर्ष किए जाने की भी घोषणा की। शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय

सहयोग पर तीन एम ओ यू तथा नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित करने पर एक एम ओ यू पर भी इस यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए।

सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं जहाजरानी मंत्री श्री नितिन जयराम गडकरी ने 15 और 16 जून, 2015 को भूटान का दौरा किया। 15 जून 2015 को चार देशों के परिवहन मंत्रियों द्वारा बी बी आई एन मोटर वाहन करार पर हस्ताक्षर किए गए।

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री सुदर्शन भगत ने थिंपू में गरीबी उन्मूलन पर सार्क मंत्रियों की चौथी बैठक में भाग लेने के लिए 29 और 30 जुलाई 2015 को भूटान का दौरा किया।

पश्चिम बंगाल की मुख्य मुत्री सुश्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री तशेरिंग टोबगे (पी एम टी टी) के निमंत्रण पर 5 से 9 अक्टूबर 2015 के दौरान अपने शिष्टमंडल के साथ भूटान का दौरा किया।

भारत के सी ओ ए एस जनरल दलबीर सिंह ने 1 अगस्त 2014 को पदभार संभालने के बाद अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा के रूप में 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 2014 के दौरान भूटान का दौरा किया। उन्होंने भूटान के महामहिम नरेश से मुलाकात की तथा महामहिम चौथे नरेश से मुलाकात की। यात्रा से भारत और भूटान के बीच घनिष्ठ सैन्य सहयोग की परंपरा कायम रहती है तथा इससे इन संबंधों में और मजबूती आएगी।

विदेश सचिव डा. एस जयशंकर ने 01 मार्च, 2015 को भूटान का दौरा किया। उन्होंने भूटान के स्थानापन्न विदेश सचिव के साथ बैठक की तथा प्रधानमंत्री तशेरिंग टोबगे के साथ मुलाकात की। उन्होंने भूटान के लिए भारत के प्रधानमंत्री के सतत समर्थन का आश्वासन दिया तथा कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वह प्रयासरत रहेंगे। उन्होंने महामहिम नरेश जिग्मे खेसर नामगिल वांग्चुक से मुलाकात की।

25 मई 2015 को थिंपू में व्यापार एवं पारगमन पर आयोजित भारत - भूटान द्विपक्षीय बैठक में भाग लेने के लिए वाणिज्य सचिव श्री राजीव खेर ने 25 से 27 मई 2015 के दौरान भूटान का दौरा किया।

आर्थिक सहयोग

भारत और भूटान के बीच परस्पर लाभप्रद आर्थिक संबंध हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण घटक रहा है। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापार एवं विकास साझेदार बना हुआ है। भूटान में विकास से जुड़े नियोजित प्रयास 1960 के दशक के पूर्वार्ध में शुरू हुए। भूटान की पहली पंचवर्षीय योजना (एफ वाई पी) 1961 में शुरू की गई। तब से भारत भूटान की पंचवर्षीय योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देता आ रहा है। दसवीं पंचवर्षीय योजना जून, 2013 में समाप्त हुई। 10वीं पंचवर्षीय योजना

के लिए भारत की समग्र सहायता 5000 करोड़ रुपए से थोड़ी अधिक है जिसमें जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अनुदान शामिल नहीं है।

क) जल विद्युत सहयोग

हमारे दोनों देशों के बीच जल विद्युत क्षेत्र में सहयोग परस्पर लाभप्रद संबंध का सच्चा उदाहरण है। जल विद्युत हमारे द्विपक्षीय सहयोग के मुख्य स्तंभों में से एक है। कुल 1416 मेगावाट की तीन जल विद्युत परियोजनाएं (एच ई पी) - (336 मेगावाट की चूखा जल विद्युत परियोजना, 60 मेगावाट की कुरिचू जल विद्युत परियोजना और 1020 मेगावाट की ताला जल विद्युत परियोजना) पहले से ही भारत को बिजली का निर्यात कर रही हैं। वर्ष, 2008 में दोनों देशों की सरकारें वर्ष 2020 तक कम से कम 10,000 मेगावाट की जल विद्युत उत्पादन क्षमता का और विकास करने पर सहमत हुईं तथा दस और परियोजनाओं की पहचान की गई। इनमें से तीन परियोजनाएं जिनकी कुल क्षमता 2940 मेगावाट है (1200 मेगावाट की पुनातसांगचू-1, 1020 मेगावाट की पुनातसांगचू-2 और 720 मेगावाट की मांगडेचू जल विद्युत परियोजनाएं) निर्माण के अधीन है तथा वर्ष 2017-18 की आखिरी तिमाही तक इनको चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। शेष 7 जल विद्युत परियोजनाओं में से कुल 2120 मेगावाट (600 मेगावाट की खोलोंगचू परियोजना, 180 मेगावाट बुनाखा परियोजना, 570 मेगावाट की वांगचू और 770 मेगावाट की चमकारचू जल विद्युत परियोजना) पर संयुक्त उद्यम मॉडल के तहत विचार किया जाएगा। इन जे वी जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 22 अप्रैल, 2014 को दोनों सरकारों के बीच एक रूपरेखा आई जी करार पर हस्ताक्षर किया गया है। खोलोंगचू जल विद्युत परियोजना के लिए संयुक्त उद्यम के साझेदार डी जी पी सी एवं एस जे वी एन एल ने निर्माण पूर्व गतिविधियां संचालित करने के लिए एक एम ओ यू पर हस्ताक्षर किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की अपनी यात्रा के दौरान, जून, 2014 में 16 जून, 2014 को खोलोंगचू जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी। भारत के राष्ट्रपति ने नवंबर 2014 में भूटान की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान जिग्मे वांग्चुक विद्युत प्रशिक्षण संस्थान के लिए आधारशिला रखी।

भूटान की अर्थव्यवस्था के लिए विद्युत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भूटान के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 14 प्रतिशत है। यह निर्यात की सबसे महत्वपूर्ण मद है जिसका भूटान के कुल निर्यात में 32 प्रतिशत योगदान है। ड्रक ग्रीन पावर कारपोरेशन, जो देश के सभी विद्युत उत्पादन संयंत्रों का नियंत्रण करता है, देश का सबसे बड़ा करदाता है।

ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2013 - 18) : 11 वीं पंचवर्षीय योजना का कुल बजट परिव्यय 21,300 करोड़ नु है, जिसमें आत्मनिर्भरता एवं समावेशी हरित सामाजिक - आर्थिक विकास प्रमुख उद्देश्य के रूप में हैं। भारत सरकार ने भूटान की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 4500 करोड़ रूपए (2800 करोड़ रूपए परियोजना अनुबंधित सहायता (पी टी ए) के रूप में, 850 करोड़ रूपए लघु

विकास परियोजनाओं (एस डी पी) के लिए और 850 करोड़ रूपए कार्यक्रम अनुदान / विकास सब्सिडी के रूप में) की प्रतिबद्धता की है। आर्थिक उत्प्रेरण योजना के लिए 500 करोड़ रूपए की अतिरिक्त सहायता के लिए भी प्रतिबद्धता की गई है।

ग) द्विपक्षीय व्यापार

भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। भारत और भूटान के बीच एक मुक्त व्यापार व्यवस्था मौजूद है। भारत - भूटान व्यापार एवं वाणिज्य करार पर पहली बार हस्ताक्षर 1972 में हुए थे जिसे पिछली बार 10 साल की अवधि के लिए 2006 में नवीकृत किया गया। इस करार में तीसरे देशों के साथ व्यापार के लिए भूटान के पणों के लिए ड्यूटी फ्री ट्रांजिट का भी प्रावधान है। 2013 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 7287 करोड़ रुपए पहुंच या जिसमें भारत से आयात का मूल्य 4389 करोड़ रुपए था और भारत को भूटान के निर्यात का मूल्य 2898 करोड़ रुपए था जिसमें बिजली का निर्यात भी शामिल है। वर्ष, 2013 में कुल द्विपक्षीय व्यापार में लगभग 4.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

विवरण	2010	2011	2012	2013	2014
भूटान को निर्यात (भारत से आयात) (करोड़ रूपए में)	2930	3520	4180	4389	4785
भूटान के कुल आयात में प्रतिशत के रूप में भारत से भूटान को निर्यात	75.1 प्रतिशत	72.3 प्रतिशत	79.4 प्रतिशत	82.4 प्रतिशत	89.3 प्रतिशत
भूटान से आयात (भारत को निर्यात) (करोड़ रूपए में)	2600	2640	2780	2898	3180
भूटान के कुल निर्यात में प्रतिशत के रूप में भारत में भूटान से आयात	88.7 प्रतिशत	83.8 प्रतिशत	93.9 प्रतिशत	91 प्रतिशत	89.4 प्रतिशत

भूटान की ओर से भारत को जिन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है उनमें मुख्य रूप से बिजली, फेरो अलाय, कार्बाइड, बार एवं राड, सीमेंट, कॉपर वायर, लोहा एवं अलौह इस्पात से बने अर्ध निर्मित उत्पाद, डोलोमाइट, जिप्सम, कृषि उत्पाद जैसे कि संतरा, इलायची और आलू शामिल हैं। भारत की ओर से भूटान को जिन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है उनमें मुख्य रूप से हाई स्पीड डीजल, लौह उत्पाद, मोटर स्पिरिट तथा एविएशन स्पिरिट (पेट्रोल), चावल, लौह अपशिष्ट एवं स्क्रैप, लकड़ी के तारकोल, हाइड्रोलिक टर्बाइन, कोयला, ब्रिकेट और कोयला के समान ठोस ईंधन, कोक तथा कोयला के सेमी कोक, लोहा एवं अलौह इस्पात के बार एवं रॉड, लोहा एवं अलौह स्टील की नालीदार शीट, सोयाबीन तेल, दूध पाउडर आदि शामिल हैं।

शैक्षिक एवं सांस्कृतिक सहयोग

भारत और भूटान के बीच शिक्षा एवं संस्कृति के क्षेत्रों में घनिष्ट द्विपक्षीय सहयोग है।

भारत की उच्च शिक्षा संस्थाओं में हर साल अवर स्नातक एवं स्नात्कोत्तर स्तरों पर भूटान के छात्रों को भारत सरकार की छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। नेहरू - वांगचुच छात्रवृत्ति स्कीम (जिसे वर्ष

2010 में कार्यान्वित किया गया) के तहत तथा नई भूटान - आई सी सी आर छात्रवृत्ति स्कीम (जिसे वर्ष 2012 में कार्यान्वित किया गया) के तहत भूटान के 67 छात्र भारत में स्नातक / स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर रहे हैं। शैक्षिक सत्र 2014-15 के लिए, 89 अवर स्नातक छात्रवृत्तियां तथा 20 भूटान - आई सी सी आर छात्रवृत्ति नामिति चुने गए हैं तथा भारत की विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में उनको भेजने की प्रक्रिया चल रही है। भारत में पढ़ने वाले भूटान के योग्य तथा स्व - वित्त पोषण के तहत अध्ययन करने वाले छात्रों को राजदूत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पिछले दस वर्षों में, भूटान के 3000 से अधिक छात्र राजदूत छात्रवृत्ति स्कीम से लाभांवित हुए हैं। भूटान के छात्रों के लिए भारत के सैनिक स्कूलों में छठवीं कक्षा के स्तर पर हर साल 10 सीटें प्रदान की जाती हैं। 12वीं कक्षा तक सैनिक स्कूल में उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च भारत सरकार उठाती है। भारत से तीन व्याख्याता टी सी एच कोलंबो योजना के तहत भूटान के दो कालेजों एवं शाही विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस स्कीम के तहत भारत से 27 और व्याख्याता के लिए भूटान की शाही सरकार का अनुरोध विचाराधीन है। भूटान के नागरिकों द्वारा कुल 269 स्लाटों का उपयोग किया गया - आईटीईसी कार्यक्रम (220 स्लॉट) तथा कोलंबो योजना की तकनीकी सहयोग स्कीम (60 स्लॉट) जो सरकारी / अर्ध सरकारी / निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के प्रशासनिक एवं तकनीकी कौशलों के उन्नयन के लिए वित्त वर्ष 2013-14 में भूटान को प्रदान की गईं।

भारत - भूटान प्रतिष्ठान

वर्तमान नरेश (उस समय क्राउन प्रिंस) की यात्रा के दौरान अगस्त, 2003 में भारत - भूटान प्रतिष्ठान की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य शिक्षा, संस्कृति, वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान एवं पर्यावरण संरक्षण जैसे फोकस वाले क्षेत्रों में जन दर जन आदान - प्रदान में वृद्धि करना है। भारत और भूटान के राजदूत इस प्रतिष्ठान के सह अध्यक्ष हैं। भूटान की शाही सरकार तथा भारत सरकार द्वारा भारत - भूटान प्रतिष्ठान के लिए मुख्य कारपस फंड के रूप में 5 - 5 करोड़ रूपए का योगदान किया गया है तथा 10 करोड़ रूपए की संपूर्ण राशि को भूटान में सावधि जमा के रूप में रखा गया है। सावधि जमा पर जो ब्याज मिलता है उसका प्रयोग भूटान / भारत के नागरिकों तथा गैर सरकारी संगठनों से ऐसे कार्यों के लिए प्राप्त प्रस्तावों के वित्त पोषण के लिए किया जाता है जिससे प्रतिष्ठान के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। निदेशक मंडल की 14वीं बैठक 11 मार्च, 2015 को थिंपू में हुई।

भूटान में हर साल 'माउंटेन इको' नामक एक साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। भारत - भूटान प्रतिष्ठान द्वारा सह प्रायोजित साहित्य महोत्सव माउंटेन इको के पांचवें संस्करण का आयोजन थिंपू में 19 से 22 अगस्त, 2015 के दौरान किया गया। महोत्सव में भारत, भूटान और अंतर्राष्ट्रीय लेखकों, फिल्म निर्माताओं, संगीतकारों एवं कलाकारों ने भाग लिया।

नेहरू - वांगचुक सांस्कृतिक केंद्र

दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान - प्रदान बहुत जीवंत है। थिंपू स्थित नेहरू - वांगचुक सांस्कृतिक केंद्र पूरे साल सांस्कृतिक गतिविधियों से परिपूर्ण रहता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत, तबला एवं योग की नियमित कक्षाएं इस केंद्र में आयोजित की जाती हैं। नेहरू - वांग्चुक सांस्कृतिक केन्द्र सांस्कृतिक समारोहों, प्रदर्शनियों, बालीवुड मूवी शो, सेमिनार आदि का भी आयोजन करता है।

भारतीय समुदाय

भूटान में तकरीबन 60,000 भारतीय नागरिक रह रहे हैं जो अधिकांशत: जल विद्युत परियोजनाओं तथा निर्माण उद्योग में काम करते हैं। इसके अलावा सीमावर्ती कस्बों में हर रोज 8000 से 10000 दिहाड़ी मजदूर भूटान में प्रवेश करते हैं और वापस आते हैं।

(08 दिसंबर, 2015)